



राज्यों की कोशिशें

राज्य सरकारें इस कोशिश में हैं कि लॉकडाउन खत्म होते-होते यह काम कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों की सरकारों ने बसें भेजकर अपने मजदूरों को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी है।

भारत डोगरा।

कोरोना वायरस से पैदा हुए संकट की मार यूं तो समाज के हर वर्ग पर पड़ी है, लेकिन मजदूर-कामगार वर्ग इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ है। उसका कामकाज छिन गया है। उसे बिना किसी साधन के बेहद कठिन परिस्थितियों में अपने घर लौटना पड़ा। एक बड़ा हिस्सा रास्ते में ही फंसकर रह गया। जो घर में हैं, उनके सामने भी रोजी-रोटी की समस्या है। वे किसी तरह अपना पेट भर रहे हैं, उनमें से बहुतों को खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा। उन्हें राहत पहुंचाना आज सबसे बड़ी चुनौती है। उनका जीवन तभी पटरी पर लौटेगा जब उन्हें फिर से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मजदूरों के जीवन में आई अस्त-व्यस्तता ने पूरी अर्थव्यवस्था के सामने संकट पैदा

कर दिया है। बड़े पैमाने पर कारखाने बंद हैं क्योंकि मजदूर नहीं हैं। इसके चलते कई जरूरी चीजों की आपूर्ति भी ठप है। कई जगह खेतों में फसलें खड़ी हैं। उनकी कटाई नहीं हो पा रही क्योंकि मजदूर नहीं हैं। इस संकट को तभी दूर किया जा सकता है जब मजदूर अपने ठिकानों पर पहुंचें और उन्हें काम उपलब्ध हो। इसलिए राज्य सरकारों की सबसे बड़ी चिंता अभी जहां-तहां फंसे अपने मजदूरों को वापस बुलाने की है। राज्य सरकारें इस कोशिश में हैं कि लॉकडाउन खत्म होते-होते यह काम कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों की सरकारों ने बसें भेजकर अपने मजदूरों को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ समन्वय बनाकर करीब 10 हजार श्रमिकों

को उनके घर पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा सरकार ने यूपी के मजदूरों को उनके राज्य की सीमा पर ले जाकर छोड़ दिया था, जिसके बाद योगी सरकार अपनी बसों से उन्हें घर छोड़ रही है। जल्द ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार के भी फंसे हुए मजदूरों को वापस लाने के लिए राज्य सरकारें कदम उठा सकती हैं। उनकी तरफ से प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग भी केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पंजाब, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने केंद्र सरकार से इसके लिए विशेष नीति बनाने की मांग की है। मजदूरों के लिए जो भी संभव हो, तत्काल करने की जरूरत है। प्रवासी मजदूरों का बड़ा वर्ग तो

अपने-अपने प्रदेशों में लौट गया है या लौट रहा है, लेकिन जो शहरों में ही रह रहे हैं उनकी समस्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। दरअसल शहरी निर्धन वर्ग की दो श्रेणियां हैं। इनमें पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं जो लंबे समय तक दिल्ली व मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने के कारण इनमें रच-बस गए हैं। यहां उनका अपना घर या अपनी झुग्गी है। यहां उनके अनेक घनिष्ठ संपर्क और संबंध हैं।

लॉकडाउन जैसे संकट के दौर में उनकी आजीविका अस्त-व्यस्त होती है तो भी अपने संपर्कों-संबंधों के आधार पर वे बहुत शीघ्र भुखमरी की स्थिति में नहीं आते हैं। लेकिन दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग हैं जो बहुत अल्पकालीन रोजगार या विशेष ठेके के अंतर्गत यहां आते हैं।

अनुभव

अशोक बोहरा। भावनात्मक स्तर पर चिंता, ऊब, अधिगिरता, असहजता का अनुभव भी आप कर सकते हैं। आप यह महसूस करेंगे कि ये सभी भावनाएं बेवजह आपके भीतर उमड़ रही हैं, जिनका आपके जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। प्रारंभिक वास्तविकता आपके भीतर है... जो बाहर है वह गौण है। इन सवालों का उसी समय जवाब देना जरूरी नहीं है... अपने भीतर ध्यान दें कि आपके मस्तिष्क में किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपनी देह की तरफ ध्यान केंद्रित करें... क्या कोई समस्या है? अगर आपको लगे कि आपके भीतर न्यूनतम स्तर पर भी असहजता है, तो यह जानने की कोशिश करें कि आप अपने जीवन को किस तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। गीता में लिखा है कि जब कभी अनैतिकता बढ़ती है और चरम पर पहुंचती है, तो पूरा तंत्र एक परम प्रक्रिया के निमाण के लिए तैयार हो जाता है जिससे कि समस्त क्रम पुनः निर्मित होते हैं।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

मुसीबत में परिवार

भारत के लगभग सभी शहरों में बहुत से आश्रयविहीन लोग भी हैं जो दिन में छोटी-मोटी मजदूरी कर फुटपाथ अथवा रैनबसेरों में अपनी रातें गुजारते हैं। लॉकडाउन से इन लोगों पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है। हाल के दंगों और हिंसा के दौरान ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जिनकी आजीविका नष्ट हो गई और मकान या आश्रय भी दंगों में जला दिए गए। ऐसे लोगों पर यह लॉकडाउन असहनीय कठिनाइयां लेकर आया है इसलिए उनके लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। ग्रामीण निर्धन बस्तियों एवं शहरी झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले अनेक परिवार ऐसे हैं जो सामान्य समय में भी अपनी न्यूनतम जरूरत-भोजन, साफ पानी और स्वच्छता से जुड़ी आवश्यकताओं के अभाव से जूझते हैं। इनके साथ ही अत्यधिक निर्धन व्यक्ति, अकेले वृद्ध, विधवा अथवा एकल महिला, विकलांगता प्रभावित व्यक्ति, दीर्घकालीन गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्ति और मानसिक रोगी भी हैं जो लॉकडाउन के दौरान बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और उनके लिए विशेष सहायता की जरूरत है। गांवों में और शहरों में भी बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो जरूरत का सामान स्टॉक करने में सक्षम नहीं होते और प्रायः उनके पास खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी खाद्य सामग्री अधिक दिनों के लिए होती ही नहीं है। उनके यदि सस्ते राशन के कार्ड बने भी हैं तो उनमें से अनेक बायोमैट्रिक मिलान की मजबूरी के चलते राशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या राशन कार्ड में उनके परिवार के सभी सदस्यों के नाम नहीं जुड़ सके हैं। साथ ही बहुत से परिवार निर्धनता में रहने के बावजूद राशन कार्ड प्राप्त नहीं कर सके हैं। कुछ परिवारों के राशन कार्ड नामालूम वजहों से निरस्त भी हो गए हैं। उनके सामने मुसीबतें आ सकती हैं।

शुरु-शुरु में यह अटपटा जरूर लगा, पर आज यह स्वाभाविक लगने लगा है क्योंकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। जल्दी ही यह सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा।

जज्बा बना रहना चाहिए

निरज वर्मा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से जूझ रहे देशवासियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें लंबी लड़ाई के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहने को कहा है। रेडियो कार्यक्रम मन की बात में उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ देश की जनता पूरी दृढ़ता से लड़ रही है।

हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। यह जज्बा बना रहना चाहिए। आज भले ही कारोबार हो, कार्यालय हो, शिक्षा या चिकित्सा हो, हर क्षेत्र महामारी के बाद की दुनिया में बदलावों के अनुरूप ढल रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम बचाव के लिए नई चीजें अपना रहे हैं, जैसे मास्क। शुरु-शुरु में यह अटपटा जरूर लगा, पर आज यह स्वाभाविक लगने लगा है क्योंकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। जल्दी ही यह सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा।

इसी तरह थूकने पर प्रतिबंध रहा है, लेकिन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया था। अब उसे स्वीकार किया जा रहा है। इसी तरह अब आपस में दो गज की दूरी बनाई जा रही है। इन सब का चलन अब जरूरी हो गया है।

दरअसल प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर है कि कोरोना का संकट लंबा चलने वाला है।



लिहाजा इससे लड़ने के लिए हमें जीवन शैली में आमूल बदलाव करना होगा। लॉकडाउन की एक सीमा है। आज न कल उसे हटाना ही होगा क्योंकि उसकी वजह से जीवनयापन पर ही संकट आ सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि लॉकडाउन हटने के बावजूद हमें कई बंदिशों के बीच रहना होगा और हम इन्हें पाबंदी मानने की बजाय जीवन

पद्धति का हिस्सा मानें, इन्हें आत्मानुशासन का रूप दे दें।

गौरतलब है कि पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी संकेत दिया था कि कोरोना वायरस का संकट अभी लंबा चलेगा। इसलिए कई अन्य देशों ने भी कई पाबंदियों के साथ धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। भारत में भी लॉकडाउन के बीच अनेक क्षेत्रों को छूट दी गई है। अभी कुछ और क्षेत्रों को खोलने की जरूरत महसूस की जा रही है। यह तभी संभव है जब काफी सतर्कता बरती जाए क्योंकि संक्रमण के मामलों का बढ़ना जारी है। इसलिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सावधान करते हुए कहा कि हम कतई अति-आत्मविश्वास में न फंस जाएं, हम ऐसा विचार न पाल लें कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे दफ्तर में अभी तक कोरोना नहीं पहुंचा है, इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है।

ऐसी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ कह रहा है। सच कहा जाए तो प्रधानमंत्री ने सकारात्मकता का संदेश दिया है। उन्होंने देशवासियों को पूरे हौसले, सावधानी और नए तौर-तरीकों के साथ कोविड-19 के खिलाफ जंग में उतरने के लिए कहा है। उम्मीद है लोग उनकी बात को समझेंगे और वे गलतियां नहीं दोहराएंगे जो इस लड़ाई को कमजोर करती हैं।

अष्टयोग-5037									
	2	4			5	3			
7	26		31	2	36	4			
	5	1				7			
6	32		29		37	6			
2	3		4	1					
	34	3	36	5	32				
	5	7				2	1		

अष्टयोग 5036 का हल									
5	6	2	4	1	7	3			
7	35	3	31	5	27	1			
4	1	7	6	3	5	2			
3	31	6	40	2	30	7			
2	3	5	7	4	1	6			
1	27	4	37	6	35	5			
6	5	1	3	7	2	4			

अपना ब्लॉग

संवेदनशीलता दिखाने का यही वक्त
मोहन। प्रायः बहुत से मजदूर एक कमरे में किराये पर रहते हैं और स्थानीय शक्तिशाली मकान मालिक उनसे कमी भी कमरा खाली करवा सकते हैं। इनके पास न तो बचत है और न ही कोई खाद्य भंडार। यहां तक कि उनके पास कोई रसोई भी नहीं है और वे आसपास छोटे-छोटे ढाबों में खाना खाते हैं। इन लोगों को तुरंत बड़े पैमाने पर सहायता देने की जरूरत है। ऐसी सहायता दी भी जा रही है पर इसे कहीं अधिक बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि यथासंभव लॉकडाउन के समय किसी को भी मजदूरी या वेतन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इन सब पर स्थानीय प्रशासन को नजर रखनी होगी और तत्काल राहत पहुंचानी होगी। सही मायने में आज प्रशासन के लिए एक परीक्षा है। निर्धन वर्ग के प्रति संवेदनशीलता दिखाने का यही वक्त है। उनका न तो अपने रोजगारदाता से गहरा संबंध है, न ही अपने आस-पड़ोस से कोई उटना-बैठना है।

